भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं.2836**
वाणिज्य विभाग

दिनांक 20 दिसंबर, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

आन्ध्र प्रदेश की निर्यात वृद्धि

2836. श्री एम. वी.वी सत्यनारायणः

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आन्ध्र प्रदेश के भीतर निर्यात वृद्धि के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या पहल की गई है;

(ख) आन्ध्र प्रदेश में इसके लिए अब तक स्वीकृत, आबंटित और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) निर्धारित लक्ष्य और तब तक प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना योजना (टीआईईएस) के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में अनुमोदित परियोजनाओं के लिए प्रदान की गई निधियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) आन्ध्र प्रदेश राज्य सहित देश में निर्यात वृद्धि के लिए सरकार द्वारा की गई प्रमुख पहलें निम्नानुसार हैं:

(i) वाणिज्य विभाग, भारत सरकार निर्यात की वृद्धि के लिए उपयुक्त बुनियादी ढांचे के सृजन में केन्द्र और राज्य सरकार की एजेंसियों की सहायता करने के उद्देश्य से वित्त वर्ष 2017-18 से केन्द्रीय क्षेत्र की एक योजना 'निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना योजना (टीआईईएस)' नामक एक योजना कार्यान्वित कर रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत निर्यात अवसंरचना की स्थापना अथवा उन्नयन के लिए केन्द्र/राज्य सरकार के स्वामित्व वाली एजेंसियों को सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ii) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के पास निर्यात संबंधी अवसंरचना को बढ़ाने, क्रेता विक्रेता बैठकों में भाग लेने आदि के लिए सम्पूर्ण भारत के निर्यातकों को सहायता प्रदान करके कृषि उत्पादों के निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए वित्तीय सहायता के लिए केंद्रीय क्षेत्र की एक विशिष्ट स्कीम है।

(iii) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) मूल्य वर्धन के लिए अवसंरचना सुविधा का उन्नयन करके, मिनी प्रयोगशाला की स्थापना करके और आन्ध्र प्रदेश सहित अखिल भारतीय आधार पर जलकृषि उत्पादन में सहायता करके समुद्री खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सहायता स्कीमें संचालित करता है।

(iv) बागान बोर्ड (चाय बोर्ड, कॉफी बोर्ड, रबड़ बोर्ड और मसाला बोर्ड) निर्यात संवर्धन के लिए विभिन्न कार्यकलाप कर रहे हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्यात के लिए सहायता प्रदान करना, व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों में भागीदारी करना, ब्रांड संवर्धन करना, क्रेता-विक्रेता बैठकें और आन्ध्र प्रदेश सहित देश भर में बाजार संपर्क करना शामिल हैं।

(ख), **(ग) और (घ):** टीआईईएस स्कीम आंध्र प्रदेश सहित अखिल भारतीय आधार पर कार्यान्वित की गई है। टीआईईएस के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में 05 अनुमोदित परियोजनाओं के लिए 76.07 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है और 60.45 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

चूंकि एपीडा, एमपीईडीए और बागान बोर्डों द्वारा कार्यान्वित योजनाएं अखिल भारतीय हैं , इसलिए कोई राज्य विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। हालाँकि, आंध्र प्रदेश के लिए विशिष्ट कुछ गतिविधियाँ/उपलब्धियाँ **अनुबंध** में हैं।

उपरोक्त पहलों ने आंध्र प्रदेश से निर्यात बढ़ाने में योगदान दिया है। पिछले 03 वर्षों और चालू वर्ष (सितंबर,2023 तक) में आंध्र प्रदेश से कुल निर्यात निम्नानुसार है

वित्त वर्ष	**निर्यात मूल्य (मिलियन अमरीकी डालर में)**
2020-21	16842.34
2021-22	19311.78
2022-23	19860.62
2023-24 (अप्रैल से सितंबर)	10312.62

स्रोत: डीजीसीआईएस

अनुबंध

लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2836 के भाग (ख), (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क्र.सं.	संगठन का नाम	उपलब्धियों
1.	एपीडा	• कृषि और खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए बुनियादी ढांचे की सुविधा के निर्माण और कृषि उड़ान योजना के उपयोग करने से संबंधित मुद्दों का हल करने के लिए , एपीडा ने क्षेत्र से निर्यात संवर्धन की सुविधा के लिए एएआई विशाखापत्तनम और विभिन्न एयरलाइनों के साथ एसोसिएट किया। • आईटीडीए पडेरू अराकू क्षेत्र, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में किसानों के साथ एक संवादात्मक बैठक और क्षेत्र का दौरा का आयोजन इस क्षेत्र से कृषि उत्पादों के निर्यात की संभावनाओं का पता लगाने के लिए किया गया था। • आंध्र प्रदेश राज्य से पारंपरिक कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के अलावा एपीडा ने जैविक प्रमाणीकरण पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। • अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए , आंध्र प्रदेश के निर्यातकों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लिया, जिसमें एपीडा ने गल्फूड 2023, सियोल फूड एंड होटल कोरिया, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 आदि में भाग लेने की सुविधा प्रदान की और निर्यातकों को आम, बाजरा, प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों आदि को बढ़ावा देने के अवसर प्रदान किए गए। • एपीडा ने कोरिया गणराज्य, जापान, ईरान, भूटान, जर्मनी, कुवैत, उज्बेकिस्तान स्थित भारत के संबंधित दूतावासों के साथ आम संवर्धन कार्यक्रम चलाया, जिसमें आंध्र प्रदेश के आमों को भी बढ़ावा दिया गया। • श्रीअन्न निर्यात संवर्धन कार्यनीति के एक भाग के रूप में, एपीडा ने आन्ध्रप्रदेश के निर्यातकों सहित श्रीअन्न के 60 प्रदर्शको और 36 अन्तर्राष्ट्रीय क्रेताओं के साथ बीएसएम का आयोजन 05 दिसम्बर, 2023 को आई वाईओएम का प्री-लांच आयोजन किया। आंध्र प्रदेश के श्रीअन्न उत्पादकों के एफपीओ ने अपने उत्पादों का इस आयोजन में संवर्धन किया। • एपीडा ने आंध्र प्रदेश के निर्यातकों, एफपीओ, स्टार्ट-अप को 3-5 नवंबर 2023 तक नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में भाग

		लेने और प्रदर्शन करने की सुविधा प्रदान की। • एपीडा नियमित रूप से आंध्र प्रदेश के निर्यातकों के साथ बैठक आयोजित करता है ताकि उनके सामने आने वाले व्यापार मुद्दों का समाधान किया जा सके।
2.	एमपीईडीए	• एमपीईडीए ने भीमावरम और नेल्लोर में दो गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं, जो राष्ट्रीय अवशेष नियंत्रण योजना (एनआरसीपी) और जलीय कृषि उत्पादों के लिए पूर्व-निर्यात परीक्षण (दोनों गुणवत्ता आश्वासन के लिए) को लागू करने में शामिल हैं। • एमपीईडीए क्लोरैम्फेनिकॉल और नाइट्रोफ्यूरन मेटाबोलाइट्स जैसे प्रतिबंधित एंटीबायोटिक अवशेषों की उपस्थिति के लिए जलीय कृषि उत्पादों (झींगा/मछली) की प्री-हार्वेस्ट स्क्रीनिंग करने के लिए राज्य में सात एलिसा स्क्रीनिंग प्रयोगशालाएं संचालित करता है। • एमपीईडीए सोसायटी राजीव गांधी सेंटर फॉर एक्वाकल्चर (आरजीसीए) बीज उत्पादन के लिए कृष्णा जिले के मणिकोंडा में गिफ्ट (तिलापिया) परियोजना संचालित करती है और टाइगर झींगा के एसपीएफ ब्रूडस्टॉक के उत्पादन के लिए विशाखापत्तनम के बीमिली में टीएएसपीएआरसी परियोजना संचालित करती है। • (एमपीईडीए) राज्य में विजयवाड़ा, भीमावरम और विशाखापत्तनम में तीन कार्यालय संचालित करता है। • पिछले पांच वर्षों के दौरान एमपीईडीए ने आंध्र प्रदेश में मूल्य संवर्धन योजनाओं के तहत 27 लाभार्थियों को 30.33 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की। • आंध्र प्रदेश से समुद्री खाद्य निर्यात ने अमेरिकी डॉलर में मूल्य के संदर्भ में 2022-23 में देश से कुल समुद्री खाद्य निर्यात में लगभग 1/3 हिस्सेदारी का योगदान दिया।
3.	बागान बोर्ड	आंध्र प्रदेश में गुंटूर में स्पाइस बोर्ड द्वारा एक गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला (क्यूईएल) और एक स्पाइस पार्क स्थापित किया गया है जो मसालों के निर्यात को सुविधाजनक बनाने में मदद करता है। स्पाइस बोर्ड आंध्र प्रदेश राज्य में मिर्च और अन्य मसालों के हितधारकों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है ।

****